

भारत में ई-अपशषिट प्रबंधन

प्रलिस के लयः

[इंडयन सेलयुलर एंड इलेक्ट्रॉनकिस एसोसएशन \(ICEA\)](#), [सरकुलर इकॉनमी](#), [ई-अपशषिट प्रबंधन](#), [वसतारतः उत्पादक उत्तरदायतः \(EPR\)](#), ई-अपशषिट (प्रबंधन) नयः, 2022

मेन्स के लयः

भारत में ई-अपशषिट प्रबंधन की स्थतः

[स्रोतः द हदः](#)

चरचा में कयों?

[इंडयन सेलयुलर एंड इलेक्ट्रॉनकिस एसोसएशन \(ICEA\)](#) ने 'भारतीय इलेक्ट्रॉनकिस सेक्टर में [सरकुलर इकॉनमी](#) के रास्ते' शीर्षक से एक वयापक रपौरट जारी की है।

- यह रपौरट [ई-अपशषिट प्रबंधन](#) पर पुनर्वचार करने और इसकी क्षमता का दोहन करने के अवसरों का पता लगाने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
- रपौरट बताती है कयः यह परवर्तन अतरकः 7 बलयन अमेरिकी डॉलर के बाज़ार का अवसर खोल सकता है।

रपौरट के प्रमुख बडुः

- भारत में ई-अपशषिट परदृश्यः
 - ICEA रपौरट के अनुसार, भारत में ई-अपशषिट प्रबंधन मुख्य रूप से अनौपचारकः है, लगभग 90% ई-अपशषिट संग्रह और 70% रीसाइकलंग का प्रबंधन प्रतःसःपद्धी अनौपचारकः क्षेत्र द्वारा कया जाता है।
 - अनौपचारकः क्षेत्र पुराने इलेक्ट्रॉनकः उपकरणों को स्पेयर पार्ट्स को सहेजने और लाभप्रद ढंग से मरमत करने में उत्कृष्टता प्राप्त है।
 - मुरादाबाद जैसे औद्योगकः केंद्र सोने और चाँदी जैसे मूल्यवान सामग्री नकालने के लयः [प्रटिड सर्कटः बोर्ड \(PCB\)](#) के प्रसंकरण में वशेषज्ञ हैं।
- सरकुलर इकॉनमी प्रसःपःलसः
 - रपौरट में ई-अपशषिट प्रबंधन के दृष्टकः को एक सरकुलर इकॉनमी स्थापतः करने की दशा में बदलने की आवश्यकता पर ज़ोर दया गया है।
 - चीन एक उदाहरण के रूप में कार्य करता है, जो वर्ष 2030 तक नए उत्पादों के नरःमाण में 35% माध्यमकः कच्चे माल का उपयोग करने का लक्ष्य रखता है, जो सरकुलर इकॉनमी दृष्टकः को दर्शाता है।
 - ई-अपशषिट में सरकुलर इकॉनमी हेतु प्रस्तावतः रणनीतयः ICEA रपौरट भारत में ई-अपशषिट के लयः सरकुलर इकॉनमी की शुरुआत करने हेतु कई प्रमुख रणनीतयः की रूपरेखा प्रस्तुत करती हैः
 - [सारवजनकः-नजी भागीदारी \(PPP\)](#): रवरः आपूर्तः शृंखला स्थापतः करने की लागत को वतःरतः करने के लयःसरकारी नकःयों और नजी उद्यमों के बीच सहयोग आवश्यक है।
 - इस जटःलः प्रयास में उपयोगकर्तःताओं से उपकरण एकत्र करना, वयक्तगः डेटा को मःटाना और उन्हें आगे की प्रकरयः और रीसाइकलंग के लयः चैनल करना शामिल है।
 - [ऑडःटःबल डेटाबेस](#): रवरः सप्लाई चैन प्रकरयः के माध्यम से एकत्र की गई सामग्रयः के पारदर्शी और ऑडःटःबल डेटाबेस का नरःमाण जवाबदेही एवं ट्रेसेबःलःटः को बढ़ा सकता है।
 - [भौगोलकः कलस्टर](#): भौगोलकः कलस्टर स्थापतः करना जहाँ बेकार पडे उपकरणों को एकत्रतः कया जाता है और नष्ट कया जाता है, रीसाइकलंग प्रकरयः को अनुकूलतः कया जा सकता है, जसःसे यह अधिक कुशल तथा लागत प्रभावी बन जाती है।

- 'उच्च-उत्पादन' पुनर्चक्रण केंद्रों को प्रोत्साहित करना: उच्च-उत्पादन पुनर्चक्रण सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित करने से अर्द्धचालकों में दुर्लभ पृथ्वी धातुओं सहित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से मूल्यवान नषिकर्षण को अधिकतम करने में मदद मिल सकती है।
- मरम्मत और उत्पाद की दीर्घायु को बढ़ावा देना: नीतितगत सफाई में मरम्मत को प्रोत्साहित करना और उत्पादों को लंबे समय तक संचालित होने में सक्षम बनाना शामिल है।
 - इसमें उपयोगकर्ता के मरम्मत के अधिकार का समर्थन करना, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के पर्यावरणीय बोझ को कम करना शामिल हो सकता है।

नोट: एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में तयकृत इलेक्ट्रॉनिक्स को या तो स्टैंड-अलोन उपकरणों के रूप में या उनके घटकों और कीमती धातुओं को नए हार्डवेयर में पुनः पेश करके एक नया जीवन दिया जा सकता है।

- इससे पृथ्वी पर उत्पादित सभी सामग्रियों को अपशिष्ट के बजाय मूल्यवान संसाधनों के रूप में आयाम मलिंगा।

भारत में ई-अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति:

- ई-अपशिष्ट का परिचय:
 - ई-अपशिष्ट में सीसा, कैडमियम, पारा और निकल जैसी धातुओं सहित कई जहरीले रसायन होते हैं।
 - भारत में ई-अपशिष्ट की मात्रा में वर्ष 2021-22 में 1.6 मिलियन टन की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
 - भारत के 65 शहर कुल उत्पन्न ई-अपशिष्ट का 60% से अधिक उत्पन्न करते हैं जबकि 10 राज्य समस्त ई-अपशिष्ट का 70% उत्पन्न करते हैं।
 - इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (ई-अपशिष्ट), एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग सभी प्रकार के पुराने, खराब हो चुके या बेकार पड़े बजिली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, जैसे घरेलू उपकरण, कार्यालय सूचना और संचार उपकरण आदिका वर्णन करने के लिये किया जाता है।
 - भारत वर्तमान में वैश्विक स्तर पर ई-अपशिष्ट के सबसे बड़े उत्पादक/जनक के रूप में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है।
- भारत में ई-अपशिष्ट प्रबंधन:
 - भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन को पर्यावरण और वन खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग/नगिरानी) 2008 विनियम के ढाँचे के अंतर्गत संबोधित किया गया था।
 - वर्ष 2011 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा शासित, 2010 के ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) विनियमों से संबंधित एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया था।
 - **वसितारति उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR)** इसकी मुख्य विशेषता थी।
 - ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 को वर्ष 2017 में अधिनियमित किया गया था, जिसमें नियम के दायरे में 21 से अधिक उत्पाद (अनुसूची- I) शामिल थे। इसमें कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (CFL) तथा अन्य पारा युक्त लैंप, साथ ही ऐसे अन्य उपकरण शामिल थे।
 - वर्ष 2018 में वर्ष 2016 के नियमों में एक संशोधन हुआ जिसने प्राधिकरण और उत्पाद प्रबंधन को बढ़ावा देने पर ज़ोर देते हुए उनके दायरे को व्यापक बना दिया।
 - उत्पाद प्रबंधन एक अवधारणा और दृष्टिकोण है जो किसी उत्पाद के निर्माण से लेकर उसके निपटान अथवा पुनर्चक्रण तक के पूरे जीवन चक्र के लिये उत्पादकों, निर्माताओं एवं अन्य हितधारकों की ज़िम्मेदारी पर ज़ोर देता है।
 - भारत सरकार ने ई-अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने और दृश्यता बढ़ाने के प्रमुख उद्देश्य के साथ ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 अधिसूचित किया।
 - यह वदियुत तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में खतरनाक पदार्थों (जैसे सीसा, पारा और कैडमियम) के उपयोग को भी प्रतिबंधित करता है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

ई-अपशिष्ट में कमी और इसके प्रभावी पुनर्चक्रण की दशा में भारत के प्रयास:

- ई-अपशिष्ट संग्रह को औपचारिक बनाना: पुनर्चक्रण प्रक्रिया को औपचारिक और मानकीकृत करने के लिये ई-अपशिष्ट संग्रह के लिये एक संपूर्ण विनियामक ढाँचे के निर्माण की आवश्यकता है, जिसमें संग्रह केंद्रों तथा पुनर्चक्रणकर्त्ताओं का अनिवार्य पंजीकरण और लाइसेंसिंग शामिल है।
- विनिर्माताओं के लिये ई-अपशिष्ट टैक्स क्रेडिट: एक टैक्स क्रेडिट प्रणाली लागू करना जो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माताओं को अधिक समय तक उपयोगी और मरम्मत योग्य सुविधाओं वाले उत्पादों को डिज़ाइन करने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करता है।
 - यह रणनीति पर्यावरण-अनुकूल डिज़ाइन तकनीकों को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।
- ई-अपशिष्ट एटीएम: सार्वजनिक स्थानों पर ई-अपशिष्ट एटीएम स्थापित करना, जहाँ कोई व्यक्ति पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जमा कर सकता है और बदले में उसे सार्वजनिक परिवहन अथवा आवश्यक वस्तुओं के लिये छोटे वित्तीय प्रोत्साहन या वाउचर प्रदान किये जा सकें।
 - इन एटीएम में शैक्षिक प्रदर्शन/डिस्प्ले भी हो सकते हैं जो ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकें।
- ई-अपशिष्ट ट्रेकिंग और प्रमाणन: इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संपूर्ण जीवनचक्र को ट्रैक करने के लिये ब्लॉकचेन-आधारित प्रणाली।

